दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्याससाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, गुरुवार 22 अप्रैल 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 201

महत्वपूर्ण एवं खास

शीना बोरा हत्याकांड में आरोपी इंद्राणी समेत जेल में बंद 39 कैदी संक्रमित

नईदिल्ली (आरएनएस)। महाराष्ट्र का कोई कोना कोरोना से खाली नहीं है. अब जेल में भी कोरोना विस्फोटक रूप ले चुका है. मुंबई के भायखला जेल में 39 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. इनमें से एक शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी भी है. मुंबई के भायखला जेल में 38 लोग कोविड 19 (ष्टश्र1द्बस्र 19) पॉजिटिव पाए गए. इन्हीं कैदियों में से एक इंद्राणी मुखर्जी भी है जो अपनी बेटी शीना वोरा के कत्ल के इल्जाम में भायखला जेल में बंद हैं. तीन दिनों पहले जेल के महिला सेल में 350 कैदियों का कोविड टेस्ट किया गया. इनमें से इंद्राणी मुखर्जी समेत 39 कैदियों में कोरोना संक्रमण पाया गया. इन सभी कैदियों को भायखला के ईएस पाटनवाला उर्दू स्कूल के कोविड सेंटर में शिफ्ट किया गया है. इस कोविड सेंटर को भायखला और आर्थर रोड जेल के महिला कोरोना संक्रमित कैदियों के लिए ही तैयार किया गया है. महाराष्ट्र में अब तक कुल 46 जेलों में 197 कैदियों को कोरोना हो चुका है. इनमें से 7 कैदियों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है. कोरोना की चपेट में सिर्फ कैदी ही नहीं हैं, 94 से ज्यादा जेल कर्मचारी भी कोविड 19 की चपेट में आ चुके हैं. इनमें से 8 जेल कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है.

एम.एस. धोनी के माता-पिता कोरोना पॉजिटिव

रांची (आरएनएस)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के माता-पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, उन्हें रांची के पल्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है. जानकारी के अनुसार, धोनी के पिता पान सिंह और माता देविका देवी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के फौरन बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया. महेंद्र सिंह धोनी फिलहाल ढ्ढक्करु में चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी कर रहे हैं. बता दें कि झारखंड में कोरोना वायरस के कारण फैला संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है. अनियंत्रित हालात पर नियंत्रण पाने के लिए झारखंड सरकार ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने का ऐलान कर चुकी है. किस दराज में गहने रखे थे। चोरी की घटना के बाद एडीएम की ओर से लालपुर थाने में एक लिखित आवेदन भी दिया गया है।

कोविंद, मोदी ने रामनवमी दी शुभकामनाएं

नईदिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी तथा कोरोना की महामारी को पराजित करने के संकल्प पर जोर दिया। कोविंद ने अपने ट्वीट में कहा, राम नवमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मदिवस पर मनाया जाने वाला यह पर्व, हमें जीवन में मर्यादा का पालन करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने आगे कहा, आइये, हम सब यह संकल्प लें कि कोविड-19 महामारी को भी हम सत्यनिष्ठा एवं संयम से पराजित करेंगे। मोदी ने कोरोना महामारी के संकट के दौर में मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के संदेश का जिक्र करते हुए महामारी से बचने के उपायों का पालन करने की अपील की।

एक दिन में पहली बार 2 हजार से अधिक मौतें

» देश में नहीं थम रहा कोरोना वायरस का कहर

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और जनमानत के लिए घातक साबित होती जा रही है। यही कारण है कि कोरोना महामारी में पिछले सभी रिकार्ड ध्वस्त हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे देश में अब तक के कोरोनाकाल में पहली बार सर्वाधिक 2023 मरीजों की मौत हुई है। जबकि एक दिन में नए कोरोना मरीजों की संख्या 2,95,041 सामने आई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के बुधवार को सामने आए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे देश में 2023 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। पिछले साल महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक एक दिन में कोरोना संक्रमितों की मौत की सर्वाधिक संख्या है। पहली बार देश में एक दिन में दो हजार से अधिक लोगों की कोरोना से मौत हुई है। इसी के साथ सक्रिय मरीजों की संख्या में भी भारी इजाफा हुआ है। इस दौरान 2,95,041 नए संक्रमित मिले। यह भी देश में एक दिन में मिले संक्रमितों की सर्वाधिक संख्या है। इसी के साथ महामारी से मरने वाले कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,82,570 हो गई है, जबकि अब तक कुल संक्रमित हुए लोगों की संख्या 1,56,09,004 है। देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 21,50,119 पर पहुंच गई। यह कुल संक्रमितों की संख्या का 13.8 फीसदी है।

85 फीसदी मरीज हुए ठीक

कोरोना संक्रमित लोगों के स्वस्थ होने की दर भी लगातार गिर रही है। यह अब 85 प्रतिशत रह गई है। आंकड़ों के मुताबिक, वायरस से स्वस्थ होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 1,32,69,863 हो गई है। हालांकि कोरोना से राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु दर गिरकर 1.20 प्रतिशत हो गई है, लेकिन महाराष्ट्र में यह दर 1.5 फीसदी और पश्चिम बंगाल में 1.6 फीसदी है।

आठ राज्यों में सबसे ज्यादा मौतें

77 फीसदी मौतें केवल आठ राज्यों में हुई हैं। देश में 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 519 लोगों की मौत महाराष्ट्र में हुई है। इसके बाद दिल्ली में 277, छत्तीसगढ़ में 191, यूपी में 162, गुजरात 121, कर्नाटक में 149, पंजाब में 60 और मध्य प्रदेश में 77 लोगों की मौत हुई। इन आठ राज्यों में कुल 1556 मौतें कुल हुई 2020 मौतों का 77.02 फीसदी है। संक्रमण के 60 फीसदी मामले छह राज्यों में मिले हैं। इस दौरान महाराष्ट्र में सर्वाधिक 62,097 नए संक्रमित मिले। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 29574, दिल्ली में 28395, कर्नाटक में 21794, केरल में 19577 और छत्तीसगढ़ में 15625 नए कोरोना मरीज मिले। पिछले एक सप्ताह से कोरोना मरीजों के मरने वालों की संख्या हर दिन बढ़ रही है। 15 अप्रैल को 1038 लोगों की मौत हुई थी और उसके बाद लगातार इस आंकड़े में इजाफा हो रहा है, जो बुधवार 21 अप्रैल को 2023 मौत सामने आई।

मसलन बीते 11 दिन में रोजाना संक्रमण के दोगुने मामले सामने आ रहे हैं। नौ अप्रैल को जहां दिनभर में 1.31 लाख लोग संक्रमित पाए गए थे, वहीं 20 अप्रैल को 2.73 लाख लोग संक्रमित पाए गए। 1761 और लोगों की मौत के बाद कई राज्यों ने आंशिक या पूर्ण लॉकडाउन लागू करने का विकल्प चुना है।

भारत में अब तक लगीं कोरोना वैक्सीन की करीब 13 करोड़ डोज, इनमें से 90 फीसदी टीके कोविशील्ड के लगाए गये

देश में अब तक लगाए कोविड-19 के करीब 13 करोड़ टीकों में से 90 प्रतिशत टीके ऑक्सफोर्ड/एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड के लगाए गए हैं। बुधवार को उपलब्ध सरकारी डेटा में यह जानकारी सामने आई। इनमें से, 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने केवल कोविशील्ड ही लगाया है जिसका उत्पादन पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) कर रहा है। भारत में दिया जा रहा दूसरा टीका हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक का स्वदेशी टीका कोवैक्सीन है। सरकार के कोविन पोर्टल पर उपलब्ध डेटा के मुताबिक कोविड-19 के कुल 12,76,05,870 टीकों में से 11,60,65,107 टीके कोविशील्ड के हैं जबकि 1,15,40,763 टीके कोवैक्सीन के हैं। इसके अलावा, गोवा, चंडीगढ़ और जम्मू-कश्मीर समेत करीब 15 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने लाभार्थियों को केवल कोविशील्ड टीका लगाया है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोवैक्सीन की तुलना में कोविशील्ड बहुत बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है जिसकी वजह से इसकी उपलब्धतता ज्यादा है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) में महामारी विज्ञान और संचारी रोग के प्रमुख डॉ समीरन पांडा ने कहा कि जल्द ही कोवैक्सीन का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। भारत बायोटेक ने मंगलवार को कहा था कि क्षमता विस्तार को बेंगलुरु और हैदराबाद के कई केंद्रों में लागू कर दिया गया है ताकि हर साल 70 करोड़ टीकों की खुराक तैयार की जा सके। बायोटेक्नोलॉजी विभाग भी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए टीका निर्माण केंद्रों को अनुदान मुहैया कराकर वित्तीय सहायता दे रहा है।

रेलवे ने महाराष्ट्र से 432 और दिल्ली से 1,166 विशेष ट्रेन सेवाओं का किया परिचालन

नईदिल्ली (आरएनएस)। यात्रियों की सुविधा के लिए भारतीय रेल देश भर में विशेष ट्रेन सेवाओं का संचालन कर रही है। इन सेवाओं में मेल/ एक्सप्रेस ट्रेन, यात्री ट्रेन और उप नगरीय ट्रेनें शामिल हैं। अप्रैल-मई, 2021 के दौरान नियमित ट्रेनों के अलावा अतिरिक्त ट्रेनों का ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों के रूप में संचालन किया जा रहा है। 20.04.2021 तक, भारतीय रेल प्रति दिन औसतन कुल 1,512 विशेष ट्रेन सेवाओं (मेल/ एक्सप्रेस और त्योहार स्पेशल) का संचालन कर रही है। इसके साथ ही कुल 5,387 उपनगरीय ट्रेन सेवाएं और 981 यात्री ट्रेन सेवाएं भी परिचालन में हैं। 21.04.021 तक, भारतीय रेल प्रति दिन उत्तरी रेलवे (दिल्ली क्षेत्र) से 53 विशेष ट्रेन सेवाओं, मध्य रेलवे से 41 विशेष ट्रेन सेवाओं और पश्चिमी रेलवे से 5 विशेष ट्रेन सेवाओं का देश के विभिन्न गंतव्यों के लिए परिचालन कर रही है। 12.04.2021 से 21.04.2021 तक की अवधि में, भारतीय रेल ने मध्य और पश्चिमी रेलवे से 432 विशेष ट्रेन सेवाओं तथा उत्तरी रेलवे (दिल्ली क्षेत्र) से 1,166 विशेष ट्रेन सेवाओं का परिचालन किया। भारतीय रेल मांग के आधार पर विभिन्न रूटों पर विशेष ट्रेनों का संचालन जारी रखेगी। भारतीय रेल यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी कि यात्री बिना किसी असुविधा के आराम से यात्रा कर सकें।

राज्यों को 400 तो निजी अस्पतालों को 600 रुपये में मिलेगी कोविशील्ड

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत तय कर दी गई है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बताया कि केंद्र सरकार के निर्देशानुसार हम कोविशील्ड वैक्सीन के दाम का एलान कर रहे हैं। राज्य सरकारों को वैक्सीन की एक डोज 400 रुपये में मिलेगी। वहीं, निजी अस्पतालों को इसके लिए 600 रुपये प्रति डोज चुकाने होंगे।

भारत में कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को तेज करते हुए 1 मई से वैक्सीनेशन का दायर बढ़ रहा है। राज्य सरकारों और प्राइवेट

अस्पतालों को वैक्सीन कितने रुपए में मिलेगी, इसका ऐलान हो गया है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्यों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए वैक्सीन के एक डोज की कीमत तय कर दी है, जिसके मुताबिक, कोविशील्ड की एक खुराक प्राइवेट अस्पताल में जहां 600 रुपए में मिलेगी, वहीं सरकारी अस्पताल में इसकी कीमत 400 रुपए होगी। यानी सरकारी अस्पताल में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग 400 रुपए देकर तो प्राइवेट अस्पताल में 600 रुपए देकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने आगे कहा कि कंपनी वैक्सीन की कुल उत्पादन का 50त्न भारत सरकार के टीकाकरण कार्यक्रम को देगी और शेष 50 फीसदी वैक्सीन राज्य सरकारों और निजी अस्पतालों के लिए होगी। बता दें कि अब तक सिर्फ भारत सरकार ही टीका खरीद रही थी, मगर अब राज्य सरकार भी टीके को खरीद सकेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जो ऐलान किया गया है, उसके मुताबिक कोविशील्ड वैक्सीन की एक खुराक का दाम राज्य सरकार के लिए (सरकारी अस्पतालों में) 400 रुपये होगा, जबकि प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए में एक खुराक मिलेगी।

छत्तीसगढ़ में वैक्सीन का भुगतान राज्य सरकार करेगी

छत्तीसगढ़ में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन का भुगतान राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार अपने नागरिकों की जीवन रक्षा के लिए हम हर संभव कदम उठाएंगे।

प्रवासी श्रमिकों के सुविधा लिए बनाए नियंत्रण कक्ष, सोशल मीडिया के जरिए अपनी समस्या बता सकेंगे मजदूर ताकि मिल सके मदद

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की परेशानियों को देखते हुए उनकी शिकायतों के समाधान के लिए 20 कंट्रोल रूम स्थापित किए हैं। कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन की आहट के कारण कई राज्यों में लगे लॉकडाउन के बाद बाद प्रवासी मजदूरों को अपने राज्यों में जाने का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। वहीं भारतीय मजदूर संघ ने भी प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर प्रवासी मजदूरों की रक्षा के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने का आग्रह किया है।

केंद्रीय श्रम मंत्रालय के अनुसार प्रवासी मजदूरों की परेशानी को देखते हुए 20 नियंत्रण कक्ष मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए हैं। पिछले साल के मुकाबले

इस बार इन नियंत्रण कक्ष में अधिकारियों की संख्या ज्यादा रखी गई है।

ये सभी कंट्रोल रूम देश भर में चीफ लेबर कमिश्नर की निगरानी में संचालित होंगे। ये कंट्रोल रूम राज्य सरकारों के साथ समन्वय कर प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगे। मंत्रालय ने आगे कहा, पीड़ित प्रवासी मजदूर, ईमेल, मोबाइल और व्हाट्सएप के माध्यम से कंट्रोल रूम में शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। ये कंट्रोल रूम लेबर इंफोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, क्षेत्रीय श्रम आयुक्त आदि स्तर के अधिकारी संचालित करेंगे। सभी संबंधित अधिकारियों से पीड़ित कामगारों को अधिकतम संभव सहायता देने का निर्देश है। साथ ही, सभी अफसरों को प्रवासी मजदूरों के मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाकर मदद करने का निर्देश दिया है। पिछले साल भी मंत्रालय ने लाखों मजदूरों की समस्याओं का कंट्रोल रूम के माध्यम से समाधान किया था।

दूसरी ओर भारतीय मजदूर संघ ने मजदूरों की परेशानी को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। भारतीय मजदूर संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री पवन कुमार ने अमर उजाला से कहा, हमने पीएमओ को पत्र लिखा है कि मजदूरों के इस पलायन का रोका जाए। वहीं लॉकडाउन के दौरान भी मजदूरों की आजीविका चलती रहे ऐसा भरोसा सरकार से मांगा है। इसके अलावा हमने सभी इंडस्ट्रीज असोसिएशन को भी पत्र लिखा है। हमने असोसिएशन से भी अनुरोध किया है कि वे अपने सदस्यों की काउंसलिंग करे और इसके उनके सदस्य मजदूरों की काउंसलिंग करें। ताकि मजदूर अपने शहरों में रुके रहें जिससे उद्योग भी चलते रहें, साथ ही मजदूरों को वेतन भी मिलता रहे और उनकी गुजर-बसर होती रहे।

जांच कमेटी ने दी क्लीन चिट राज्य सरकार को सौंपी रिपोर्ट

» विकास दुबे एनकाउंटर केस में यूपी पुलिस राहत

नईदिल्ली (आरएनएस)। कुख्यात अपराधी विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी राहत मिली है। उत्तर प्रदेश पुलिस को सबूतों के अभाव में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से क्लीन चिट मिल गई है। इस मामले की जांच करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित की गई रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान समिति ने उत्तर प्रदेश पुलिस को क्लीन चिट दे दी है। कमेटी को यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान कमेटी ने कई पुलिसकर्मियों से पूछताछ की, लेकिन उनको एक भी पुख्ता सबूत नहीं मिले, जिससे यह साबित हो सके कि एनकाउंटर फर्जी था। साक्ष्यों के अभाव में विकास दुबे एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस को क्लीन चिट दे दी। रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नही मिले हैं। आपको बता दें कि विकास दुबे एनकाउंटर केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय कमेटी की गठित की थी। कमेटी में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्तावित नामों को मंजूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर जस्टिस बीएस चौहान की अगुवाई में पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता और हाईकोर्ट के पूर्व जज शशिकांत अग्रवाल की कमेटी बनाई थी।

दिल्ली सरकार मजदूरों को देगी 5-5 हजार रुपए पलायन रोकने केजरीवाल ने गठित की कमेटी

नईदिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। दिन ब दिन इसके संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के चलते एक हफ्ते के लॉकडाउन के ऐलान के बाद बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर दिल्ली से वापस अपने घरों की ओर रवाना होना शुरू हो गए हैं। इसी बीच दिल्ली सरकार लॉकडाउन के दौरान प्रवासी, दैनिक व निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों की भलाई के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने लॉकडाडन में उनकी रहने, खाने-पीने, कपड़े व दवा इत्यादि की व्यवस्था के लिए जरूरी कदम उठाए है। दिल्ली सरकार ने उच्च न्यायालय को यह जानकारी देते हुए बताया कि प्रधान सचिव-गृह के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया है जो सभी प्रकार की व्यवस्थाएं देखेंगे।

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से लॉकडाउन के दौरान प्रवासी, दैनिक व निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों के लिए उचित कदम उठाने पर रिपोर्ट मांगी थी। सरकार ने पेश रिपोर्ट में कहा कि सरकार ने श्रमिकों की भलाई के लिए कई कदम उठाए है। सभी प्रकार की व्यवस्था देखने के लिए एक कमेटी का गठन किया है और प्रधान सचिव-गृह भूपिन्द्र सिंह भल्ला को इसका चेयरमैन बनाया गया है जो राज्य के नोडल अधिकारी रहेंगे।

वहीं दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त राजेश खुराना दिल्ली पुलिस की और से नोडल अधिकारी होंगे। कमेटी में आयुक्त श्रम को सदस्य सचिव, प्रधान सचिव श्रम-सदस्य, शिक्षा निदेशक-सदस्य, विशेष सचिव वित-सदस्य, रिवेन्यू उपसचिव-सदस्य इत्यादि शामिल है।

अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान कृषि निर्यात में करीब 18 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारत ने पिछले सालों में कृषि उत्पादों के मामले में लगातार निर्यात अधिशेष कायम रखा । 2019-20 के दौरान भारत का कृषि एवं संबद्ध जिंसों का निर्यात 2.52 लाख करोड़ रुपये और आयात 1.47 लाख करोड़ रुपये का था। यहां तक कि महामारी के कठिन समय में भी भारत ने इस बात का ध्यान रखा कि वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला टूटने न पाए और लगातार निर्यात को जारी रखा। अप्रैल 2020 से फरवरी 2021 के दौरान कृषि एवं संबद्ध जिंसों का 2.74 लाख करोड़ रुपये का निर्यातकिया गया जो पिछले साल की समान अवधि में हुए 2.31 लाख करोड़ रुपये के निर्यात के मुकाबले 18.49 प्रतिशत अधिक रहा।

निर्यात में महत्वपूर्ण सकारात्मक वृद्धि दर्शाने वाली वस्तुओं में गेहूं,अन्य अनाज, चावल(बासमती के अलावा, सोया मील, मसाले,चीनी, कपास, ताजा सब्ज़ियां, प्रसंस्कृत सब्ज़ियां और मादक पेय शामिल हैं ।

गेहूं और अन्य अनाजों के मामले में पिछले साल की तुलना में भारी वृद्धि दर्ज हुई और ये क्रमशः 425 करोड़ रुपये से बढ़कर 3283 करोड़ रुपये और 1318 करोड़ रुपये से बढ़कर 4542 करोड़ रुपये हो गई। कुछ खास देशों की मांग पर नैफेड ने जी टू जी व्यवस्था के तहत 50,000 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात अफगानिस्तान को और 40,000 मीट्रिक टन गेहूं का निर्यात लेबनान को किया।भारत ने गेहूं के निर्यात के मामले में 727 प्रतिशत की जबरदस्त वृद्धि दर्ज की।

देश ने चावल (गैर बासमती) के निर्यात के मामले में भी 132 प्रतिशतकी महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की। गैर बासमती चावल का निर्यात 2019-20 के 13,030 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 में 30,277 करोड़ रुपये हो गया ।निर्यात में यह वृद्धि कई कारकों की वजह से हुई जिनमें से मुख्य थी तिमोर-लेस्ते ,पपुआ न्यू गिनी,ब्राज़ील ,चिली और प्यूर्तो रिको के बाज़ारों पर भारत का कब्ज़ा होना। इन देशों के अलावा टोगो, सेनेगल, मलेशिया, मेडागास्कर,इराक,बांग्लादेश,मोज़ाम्बीक,वियतनाम तथा तंज़ानिया गणराज्य को भी निर्यात किया गया।

भारत ने सोया मील का निर्यात भी बढ़ाकर 132 प्रतिशत कर दिया । सोया मील का निर्यात 2019-20 के 3087 करोड़ रुपये के मुकाबले 2020-21 में 7224करोड़ रुपये हो गया ।